बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 2

मंगलवार, तिथि 07 चैत्र, 1939 (श.) / 28 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 14

1.	ऊर्जा विभाग	-	-	04
2.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	-	-	01
3.	स्वास्थ्य विभाग	-	-	09
			कुल योग –	14

विभागीय कार्रवाई

208. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्वी चम्पारण जिला में विद्युतीकरण के लिए ई.एन.सी. एवं वी.टी.एल. कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि ई.एन.सी. कंपनी जो अपने द्वारा विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराकर एवं जाली माता रानी के नाम से पेटी कन्ट्रेक्ट पर कार्य करा रही थी, जो काम कम जनता से अवैध रुपयों की उगाही करने का कार्य ज्यादा करती थी;

(ग) क्या यह सही है कि बिना विद्युतीकरण के ई.एन.सी. कंपनी को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया तथा उसे कार्य से मुक्त कर दिया गया, जो करोड़ों रुपये लेकर सरकारी राशि का गबन विभागीय उच्च पदाधिकारियों की मिलीभगत से किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ई.एन.सी. कंपनी जो बिना विद्युतीकरण के 75 प्रतिशत की राशि का गबन करने हेतु एफ.आई.आर. दर्ज करने तथा जिन पदाधिकारियों के आदेश से सरकारी राशि की लूट की गई उन पर विभागीय कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

रूमों का निर्माण

209. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय ने बिहार के 10 जिलों में अल्पसंख्यक स्कूलों के निर्माण हेतु 480 क्लास रूम बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त 10 जिलों के अल्पसंख्यक स्कूलों के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने भी 1.43 करोड़ की स्वीकृति दी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्वीकृत राशि की उपलब्धता के बाद बिहार के 10 जिलों में समय रहते अल्पसंख्यक स्कूलों का क्लास रूमों का निर्माण कराकर कक्षा में पढ़ाई कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भ्रष्टाचार पर अंकुश

210. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मौजूदा समय में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल अपने स्तर से दवा एवं सर्जिकल सामान की खरीद करते हैं, जिससे हमेशा अनियमितता होती रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग की वेबसाईट पर दवा एवं सर्जिकल सामान की खरीद के लिए ई-निविदा निकालने से बड़ी-बड़ी कंपनियों को भाग लेने का मौका मिल सकेगा और इससे राज्य सरकार की राशि की बचत भी होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में सभी मेडिकल कॉलेजों सहित सरकारी अस्पतालों के लिए विभाग की ओर से दवा तथा सर्जिकल सामान की खरीद के लिए निविदा प्रकाशित करने का विचार रखती है, ताकि बड़ी-बड़ी कंपनियां भाग ले सकें और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके?

विद्युत की आपूर्ति

211. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत पंचायत छकरबंधा ग्राम बढ़ईखाप में विद्युत आपूर्ति हेतु वायरिंग कर दिया गया परंतु आजतक ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में ग्राम बढ़ईखाप में अविलम्ब ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

वायरिंग यथाशीघ्र

212. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी प्रखंड के एकतानगर रोड नं.-1 एवं 2 में पोल पर खुला हुआ तार का वायरिंग है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना में सभी जगह कवर वायरिंग किया जा चुका है परन्तु एकतानगर में अभी तक वायरिंग का कार्य नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एकतानगर रोड नं.-1 एवं 2 में खुला पोल के तार को हटा कर कवरिंग वायरिंग यथाशीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर रिक्त

213. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में लगभग 30 से 35 प्रतिशत विभिन्न श्रेणी के पद रिक्त हैं, साथ ही राज्य में 2800 सामान्य डॉक्टरों के पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त रिक्त पदों को कबतक भरना चाहती है?

मरीजों को लाभ

214. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मोकामा रेफरल अस्पताल में पद सृजन के अनुरूप चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं यथा एक्स-रे, ई.सी.जी., खून जांच आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि अप्रैल, 2016 से जनवरी, 2017 तक कितने मरीजों को इसका लाभ मिला है?

रिक्त पदों पर बहाली

215. **श्री सूरजनंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में सामान्य चिकित्सकों के 2800 पद, विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2000 पद, ए.एन.एम. के 7000 पद तथा जी.एन.एम. के 3817 पद पिछले चार वर्षों से रिक्त हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन रिक्त पदों को कबतक भरने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

अस्पताल का निर्माण

216. **श्री विनोद नारायण झा** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल स्थापित करने का सरकार का निर्णय पूर्व से है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार के पूर्व के निर्णय के बावजूद अबतक सभी जिला मुख्यालयों में जिला अस्पताल का निर्माण नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाना चाहती है कि किन-किन जिलों में जिला अस्पताल की स्थापना अबतक नहीं हो पाई है?

प्रोन्नति देने पर विचार

217. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में करीब 21 वर्षों से डॉक्टरों की प्रोन्नति नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि 2007-08 के बाद मेडिकल शिक्षकों को नियमित प्रोन्नति नहीं मिली है;

(ग) क्या यह सही है कि डॉक्टरों एवं मेडिकल डॉक्टरों को ससमय प्रोन्नति नहीं मिलने के कारण कार्य-क्षमता क्षीण होती जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चिकित्सकों एवं मेडिकल चिकित्सकों को प्रोन्नति देना चाहती है, यदि नहीं तो क्या कठिनाइयां हैं?

एम्स अस्पताल के रूप में विकसित

218. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में भूमि, भवन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है;

(ख) क्या यह सही है कि बढ़ती हुई आबादी के कारण उत्तरी बिहार के सबसे अधिक प्रतिष्ठित अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को एम्स अस्पताल के रूप में कबतक विकसित करना चाहती है?

विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

219. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड अंतर्गत धमौन के लिए एक विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' के लिए भूमि चयन हेतु कई बार अधिकारी दल का स्थल निरीक्षण हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार धमौन विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अस्पताल की सुविधा

220. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला मुख्यालय में सरोजा सीताराम राजकीय 100 बेड अस्पताल के भवन का निर्माण वर्ष 2008 से ही चल रहा है और अभी तक निर्माण कार्य समाप्त नहीं हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर उद्घाटन की तिथि निश्चित करना चाहती है ताकि गरीब जनता को अस्पताल की सुविधा मिल सके, यदि हां तो कबतक?

अंकुश लगाने पर विचार

221. **श्री रामचन्द्र भारती**: क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सरकारी एम्बुलेंस कर्मी मरीज और उनके परिजनों को कमीशन के लिए बहला-फुसला कर मंहगे प्राइवेट अस्पतालों में ले जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि प्राइवेट एजेंट और एम्बुलेंस चालकों की मिलीभगत से प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज के परिजनों से मनमाने पैसे की वसूली कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि एम्बुलेंस कॉल के दौरान प्रति ट्रिप चार्ज 300 रुपये है, एम्बुलेंस चालकों द्वारा प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराते समय 300 रुपए की रसीद नहीं दी जाती है जिससे परिजनों को इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में नहीं बनती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में चल रहे एम्बुलेंस के इस गोरखधंधे पर अंकुश लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 28 मार्च, 2017